



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:-एफ 9()परावि/भण्डार/टोनर रिफिलिंग/2022-23/ 7/

जयपुर, दिनांक-09/3/2022

सीमित बोली सूचना

विभाग में निम्नानुसार विभागीय प्रिन्टरों/फैक्स के टोनरों की रिफिलिंग करने हेतु दिनांक 31.03.2023 तक के लिए दरें अनुमोदित की जानी है :- (अनुमानित व्यय 1.70 लाख रुपये)

क्र. सं.	वस्तु का नाम (मय विनिर्देशों) स्पेसिफिकेशन	रिफिलिंग दर प्रति नग मय जीएराटी (रु.)
1.	एच.पी. टोनर कार्टेज रिफिलिंग - 12ए, 49ए, 78ए, 505ए (05ए), 51ए, 88ए, 1007ए, प्रिन्टर टोनर कार्टेज, केनन टोनर कार्टेज रिफिलिंग- केनन 328	
2.	रीको लेजर प्रिन्टर एसपी 310 डीएन टोनर मय चिप	

नोट :-

- रिफिलिंग कार्य के अन्तर्गत जो भी कार्टेज के पार्ट्स खराब होंगे यथा, चिप, पीसीआर, ब्लेड, ड्रम, मैग्नेटिक रोड आदि बदलकर रिफिलिंग कार्य करना होगा एवं दरें सभी पार्ट सहित प्रस्तुत करनी हैं, खाली कार्टेज विभाग द्वारा दिया जावेगा एवं रिफिलिंग सचिवालय स्थित पंचायती राज विभाग जयपुर भण्डार में करनी होगी। टोनर कार्टेज एच.पी. 51ए एवं रीको लेजर प्रिन्टर एसपी 310 डीएन टोनर कार्टेज में 140 ग्राम इंक एवं शेष सभी कार्टेज में 80 ग्राम इंक डालनी होगी। कार्टेज एच.पी. 51 ए एवं रीको लेजर प्रिन्टर एसपी 310 डीएन में 1500 प्रतियां एवं अन्य सभी से 900-1000 प्रतियां साफ आनी चाहिए। इससे पूर्व कार्टेज से खराब प्रतियां आने की स्थिति में कार्टेज पुनः सही करके देना होगा जिसके लिए विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।
- फर्म को पेनकार्ड की प्रति एवं GST प्रमाण पत्र की छायाप्रति (यदि लागू हो) संलग्न की जानी आवश्यक है।
- बोलीदाता फर्म को राजकीय कार्यालय में 2 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। जिसका प्रमाण पत्र बोली के साथ संलग्न किया जावे।

अतः इच्छुक फर्म/संस्था अपनी दरें दिनांक 21.03.2022 सायं 2.30 बजे तक अपने लेटर हैड पर मय पूर्ण स्पेसिफिकेशन अंकित करते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग) सचिवालय, जयपुर स्थित कार्यालय में अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त बोलियां दिनांक 22.03.2022 को सायं 4.30 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष में उपापन समिति द्वारा खोली जावेगी। सफल निविदादाता को 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं कार्य राशि 1,70,000/- का 2.5 प्रतिशत कार्य संपादन राशि रुपये 4250/- विभाग में जमा करानी होगी।

कार्यालयाध्यक्ष

संयुक्त शारान राचित (अभ्यो-नन)।

दर संविदा की शर्तः-

टिप्पणी:- बोलीदाताओं को इन शर्तों को सावधानी पूर्वक पढना चाहिए तथा अपनी बोलियां भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए।

1. रिफ्लिंग कार्य के अन्तर्गत जो भी कार्टेज के पार्ट्स खराब होंगे यथा, चिप, पीसीआर, ब्लेड, ड्रम, मेगनेटिक रोड आदि बदलकर रिफ्लिंग कार्य करना होगा एवं दरें सभी पार्ट सहित प्रस्तुत करनी हैं,
2. खाली कार्टेज विभाग द्वारा दिया जावेगा एवं रिफ्लिंग सचिवालय स्थित पंचायती राज विभाग जयपुर भण्डार में करनी होगी।
3. टोनर कार्टेज एच.पी. 51ए एवं रीको लेजर प्रिन्टर एसपी 310 डीएन टोनर कोर्टेज में 140 ग्राम इंक एवं शेष सभी कार्टेज में 80 ग्राम इंक डालनी होगी।
4. कार्टेज एच.पी. 51 ए एवं रीको लेजर प्रिन्टर एसपी 310 डीएन में 1500 प्रतियां एवं अन्य सभी से 900-1000 प्रतियां साफ आनी चाहिए।
5. रिफ्लिंग किये हुये कार्टेज से खराब प्रतियां आने की स्थिति में कार्टेज पुनः सही करके देना होगा जिसके लिए विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।
6. फर्म को पेनकार्ड की प्रति एवं GST प्रमाण पत्र की छायाप्रति (यदि लागू हो) संलग्न की जानी आवश्यक है।
7. बोलीदाता फर्म को राजकीय कार्यालय में 2 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। जिसका प्रमाण पत्र बोली के साथ संलग्न किया जावे।
8. सफल निविदादाता को 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं कार्य राशि का 2.5 प्रतिशत कार्य संपादन राशि रुपये 4250 विभाग में जमा करानी होगी।
9. बोलियों को बोली सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करना चाहिये।
10. **अधिकृत/वास्तविक डीलरों (Bonafide dealers) द्वारा निविदाएँ :-**
बोलियां मालों के वास्तविक डीलरों द्वारा ही दी जायेगी। अतः वे एस. आर. प्रारूप 11 में एक घोषणा प्रस्तुत करेंगे।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

11. (i) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना केता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जायेगा।
(ii) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों को ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिये बाध्य नहीं हो जाते एवं केता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिये ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गई किसी भागीदार की रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिये पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होंगी।
12. बोली प्ररूप स्याही से भरा जायेगा या टंकण से भरा जायेगा। पेंसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
13. दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जायेंगी। इसमें कोई त्रुटियाँ (Errors) एवं /या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियाँ करनी हों तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिये।
14. सामान्य वित्तीय एवं लेखा अनुभाग की अधिसूचना दिनांक 19 नवम्बर, 2015 के अनुसार प्रकाशित अनुसूची 1 में उल्लेखित माल/सामग्री के संबंध में सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा प्रकाशित दरें प्रस्तुत करने पर उन पर प्राथमिकता से विचार किया जावेगा।
15. दरें गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. उद्धृत की जानी चाहिये तथा उसमें सभी अनुषंगिक (Incidental) प्रभारों को शामिल करना चाहिये। स्थानीय प्रदायों (सप्लाइज) के मामले में दरों में समस्त करों आदि को शामिल करना चाहिये तथा सरकार द्वारा कोई गाडी भाडा (कार्टेज) या परिवहन प्रभारों का सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा तथा माल की सुपुर्दगी केता अधिकारी के परिसरों पर दी जायेगी। खरीदे जाने वाले माल कार्यालयों के उपयोग के लिये होते हैं, इन पर चुंगीकर (ऑक्ट्राय) एवं स्थानीय करों को शामिल नहीं किया जायेगा। पूर्व की दशा में विहित प्रारूप में एक प्रमाण पत्र सप्लाइ आदेश के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।
16. दरों की तुलना : राजस्थान के बाहर की फर्मों द्वारा तथा राजस्थान के भीतर की उन फर्मों द्वारा, जो नियमों के अन्तर्गत मूल्य अधिमान के लिये अधिकृत नहीं हैं निविदत्त दरों की तुलना करने में GST की शर्तों को शामिल नहीं किया जायेगा।
17. मूल्य अधिमान : मूल्य अधिमानता/अधिमानता राजस्थान के उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों पर या राजस्थान के बाहर उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों की तुलना में भण्डार कर (राजस्थान के उद्योगों को अधिमानता) नियम, 1995 के अनुसार ही जायेगी।

18. विधि मान्यता : निविदाये उनके खोले जाने के दिनांक से 90 दिन की अवधि के लिये विधि मान्य होगी।
19. अनुमोदित प्रदायकर्ता (सप्लायर) के लिये यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की दशा, स्पेसीफिकेशन, साईज, मेक एवं ड्राईंग आदि की सावधानी पूर्वक जांच कर ली है। यदि उसे इन शर्तों के किसी भाग, स्पेसीफिकेशन, ड्राईंग आदि के आशय के बारे में कोई सन्देह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
20. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या उप-भाडे (सबलेट) पर नहीं देगा।
21. विशेष विवरण (स्पेसीफिकेशन) :
 - (i) प्रदाय की गई सभी वस्तुएं बोली में निर्धारित स्पेसीफिकेशन, ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होंगी तथा जहां पर वस्तुओं की आई.एस.आई. स्पेसीफिकेशन के अनुसार अपेक्षा की गई हो, उन मदों को पूर्ण रूप से उन स्पेसीफिकेशन के अनुरूप होना चाहिए तथा उस पर वह मार्क होना चाहिए।
 - (ii) तारा चिन्ह से अंकित/कम संख्या पर अंकित वस्तुओं का प्रदाय, अन्य बातों के साथ, अनुमोदित नमूनों के ठीक अनुरूप होगा तथा अन्य पदार्थों के मामलों में जहां कोई स्तरीकृत या अनुमोदित नमूना हो, अत्युत्तम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जावेगा। क्रेता अधिकारी/क्रेता समिति का इस संबंध में कि क्या प्रदाय की गई वस्तुएं स्पेसीफिकेशन के अनुरूप है, तथा या वे सैम्पल, यदि कोई हो, के अनुसार है, किया गया निर्णय निविदादाताओं के लिये अन्तिम एवं मान्य होगा।
 - (iii) वारंटी एवं गारंटी का खंड बोलीदाता यह गारन्टी देगा कि माल/स्टोर्स/वस्तुएं खरीदे जाने वाले उस माल/स्टोर्स/वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के लिये यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया हो एवं/या उन्हें अनुमोदित कर दिया हो, यदि दिनांक/माहों की उक्त अवधि में, उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं की उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गये हैं (तथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम व परिणामी) तो क्रेता उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाये जायेंगे, रद्द करने के लिये अधिकृत होगा। ऐसे रद्द किये जाने पर माल/स्टोर्स/वस्तुएं विक्रेता की जोखिम पर होगी तथा माल आदि का या उसके उस भाग को जिस क्रेता अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है बदल देगा, अन्यथा निविदादाता ऐसी क्षति के लिये भुगतान करेगा जो इसमें दी गई शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गई कोई भी बात से इस संविदा के अर्थ या अर्थों का उस संबंध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगी।

(iv) मशीनों एवं उपकरणों के मामले में भी, उक्त खण्ड (iii) में उल्लिखित किये गये अनुसार गारंटी दी जायेगी तथा बोलीदाता गारंटीकृत अवधि में पुर्जों को बदलेगा या किसी भी विनिर्माण की कमी को दूर करेगा। यदि उक्त अवधि में उन्हें वैसा पाया जायेगा ताकि मशीन एवं उपकरण ठीक काम कर सके। बोलीदाता मशीनों एवं उपकरणों को भी बदलेगा यदि वे ऐसे दोषपूर्ण पाये जाये कि विनिर्माण की त्रुटि आदि के कारण उन्हें काम में नहीं लिया जा सकता हो।

(v) क्रेता अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट मशीन एवं उपकरण के मामले में निविदादाता ऐसी शर्तों पर जो उनके बीच स्वीकार की जायेगी, वार्षिक रख-रखाव (मेन्टेनेन्स) एवं गरम्मत करने के लिये उत्तरदायी होगा। निविदादाता किसी विशिष्ट प्रकार की मशीनरी के लिए आवश्यक स्पेयर पार्ट्स एवं उपकरणों की नियमित समुचित सप्लाई करने के लिए उत्तरदायी होगा। उपकरणों की वार्षिक रख-रखाव व मरम्मत की दर संविदा के अधीन हो या अन्यथा हो। मॉडल में परिवर्तन के मामले में वह क्रेता अधिकारी को पर्याप्त समय पूर्व सूचना देगा। क्रेता अधिकारी अपनी मशीनों एवं उपकरणों को पूर्ण रूप से कार्यकारी दशा में रखने के लिए उनसे स्पेयर पार्ट्स खरीदना पसन्द कर सकेगा।

22. निरीक्षण : (क) क्रेता अधिकारी या उसका विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि सभी युक्तियुक्त उचित समयों पर प्रदायकर्ता के परिसर में जाएगा तथा वह विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद जैसा भी निश्चय किया जाएगा, किसी भी समय मालों/उपकरणों/मशीनों की सामग्री एवं कर्मकौशल का निरीक्षण एवं जांच करने की शक्ति रखेगा।

(ख) बोलीदाता अपने कार्यालय के परिसर, गोदाम एवं वर्कशाप का, जहाँ पर निरीक्षण किया जा सकता है, पूर्ण पता, उस व्यक्ति के नाम व पते के साथ देगा जिससे उस प्रयोजन के लिए सम्पर्क करना होगा। उन डीलरों के मामलों में जो व्यवसाय में नए रूप में प्रविष्ट हुए हैं, उन्हें बैकर्स से एक परिचय-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

23. सप्लाई जब भी प्राप्त की जाएगी उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वे स्पेसिफिकेशन्स के अनुरूप हैं। जहां आवश्यक हो या विहित किया गया हो या व्यावहारिक हो, वहां परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों जैसी श्री राम टेस्टिंग हाउस, नई दिल्ली एवं तत्समान परीक्षण गृहों में कराया जाएगा तथा जहां पर सप्लाई किया गया सामान इन परीक्षणों के परिणामस्वरूप विहित स्पेसिफिकेशन्स के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा, उन्हें स्वीकार किया जाएगा।

24. परीक्षण प्रभार : परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। यदि बोलीदाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता हो या यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात होता हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तरों या स्पेसिफिकेशन्स के अनुरूप नहीं है, तो परीक्षण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

25. रद्द करना : (i) निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं अनुमोदित नहीं की जाएंगी उन्हें रद्द किया जाएगा तथा बोलीदाता द्वारा उन्हें क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जाएगा।
- (ii) तथापि, यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण, पूर्ण या आंशिक रूप में उन वस्तुओं को बदलना साध्य (feasible) नहीं समझा जाए, तो क्रेता अधिकारी बोलीदाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित कि जाएंगे, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती करेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अन्तिम होगी।
26. रद्द की गई वस्तुओं को बोलीदाता उन्हें रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिवस के भीतर हटा लेगा, इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी प्रकार की हानि कमी या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसे बोलीदाता की जोखिम एवं उसके लेखे पर उन वस्तुओं को जिन्हें वह उचित समझे बेचने का अधिकार होगा।
27. बोलीदाता उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सड़क या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता की माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सकें। किसी प्रकार की हानि, क्षति, टूटफूट या रिसाव (लीकेज) या किसी कमी के होने के मामले में, निविदादाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रीयों की जांच/निरीक्षण किए जाने पर पायी गयी ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जाएगी।
28. प्रदाय हेतु संविदा को यदि माल की सप्लाई क्रेता अधिकारी की सन्तुष्टि के अनुसार नहीं की जाती है, तो बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत (repudiate) कर सकता है। यह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों अभिलिखित करेगा।
29. बोलीदाता का उसके प्रतिनिधि की ओर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक ही अनर्हता (disqualification) होगी।
30. (i) सुपुर्दगी अवधि :- बोलीदाता जिसकी बोली स्वीकार की जाएगी, वह सप्लाई आदेश की तारीख से की अवधि के भीतर तक निम्न प्रकार सामान की सप्लाई करने की व्यवस्था करेगा।

क.सं.

मद

मात्र

सुपुर्दगी अवधि

बोलीदाता के हस्ताक्षर

- (ii) मात्रा की सीमा – आदेश को फिर से देना :- यदि बोली सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के लिए आदेश दिया जाता है, तो निविदादाता अपेक्षित सप्लाई की पूर्ति करने के लिए बाध्य होगा। पुनः आदेश (Repeat Orders) भी निविदा में दी गयी शर्तों पर दिए जा सकेंगे। परन्तु शर्त यह कि ऐसे पुनरादेश मूल रूप से खरीदी गयी मात्रा की 50 प्रतिशत तक की सप्लाई के लिए ही होंगे तथा ऐसे आदेश देने की अवधि अन्तिम माल प्रदाय करने के दिनांक से एक माह से अधिक बाद की नहीं होगी। यदि निविदादाता, ऐसी सप्लाई करने में असमर्थ रहता है तो क्रेता अधिकारी अवशेष सामान की सप्लाई की व्यवस्था सीमित बोली द्वारा या अन्यथा प्रकार से करने के लिए स्वतन्त्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जायेगी उसकी बोलीदाता से वसूली की जायेगी।
- (iii) यदि क्रेता अधिकारी कि-ही निविदा वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है तो बोलीदाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने के लिए अधिकृत नहीं होगा।

(ड) (1) करार एवं प्रतिभूति निक्षेप (Agreement and Security Deposit)–

(i) सफल बोलीदाता को आदेश के प्राप्त होने के 7 दिवस की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों (स्टॉक्स) के लिए निविदायें स्वीकार की गयी हैं उनके मूल्य के 2.5 प्रतिशत के बराबर कार्य संपादन राशि रूपये 4250 जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको बोली के स्वीकार किये जाने की सूचना उसे दी गई है, 15 दिन के भीतर जमा कराई जायेगी।

(iii) कार्य संपादन राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।

(iv) कार्य संपादन राशि के रूप निम्न प्रकार होंगे–

(क) नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक/चालान की रसीदी प्रति/एफडीआर

(ख) डाकघर बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत गिरवी (pledge) रखा जावेगा।

(ग) अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डिफेन्स सेविंग्स सर्टिफिकेट्स, किसान विकास पत्र, या कोई अन्य स्क्रिप्ट/विलेख यदि उन्हें गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाणपत्रों को उनके उक्त मूल्य (सारेन्डर वैल्यू) पर स्वीकार किया जाएगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

(v) एक समय पर खरीद के मामले में कय आदेश के अनुसार मदों की अन्तिम सप्लाई से एक माह के भीतर तथा यदि सुपुर्दगी के सान्तर (staggered) किया जाता है तो दो माह के भीतर उसके लिए संविदा के संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद या गारण्टी की अवधि, यदि हो, के समाप्त होने के बाद, जो भी बाद में हो तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि बोलीदाता के विरुद्ध कोई देय बकाये (outstanding Due) नहीं है, कार्य संपादन राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।

(2) (i) निदेशक— उद्योग विभाग, राजस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत फर्मों को उन सामानों के सम्बन्ध में जिनके लिए वे रजिस्टर्ड है उनके द्वारा निदेशक उद्योग से पंजीयन की विधिवत अनुप्रमाणित एक प्रति प्रस्तुत किए जाने पर, बयाना राशि के भुगतान से आंशिक छूट दी जायेगी तथा वे निविदा के अनुमानित मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर कार्य संपादन निक्षेप का भुगतान करेंगी।

(ii) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम कार्य संपादन राशि जमा कराने से मुक्त होंगे।

(3) कार्य संपादन राशि का समपहरण — कार्य संपादन की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहत किया जाएगा —

(क) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

(ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सप्लाई संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) कार्य संपादन राशि को समपहत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(4) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जावेगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपडत (counter foil) निशुल्क प्रस्तुत की जायेगी।

31. (i) समस्त माल रेलवे या गुड्स ट्रान्सपोर्ट के जरिये भाडा चुका कर भेजा जावेगा। यदि सामान भेज दिया जाता है तथा उसका भाडा चुकाना होगा, जो प्रदायकर्ता (सप्लायर) के बिल में से उस भाडे के 5 प्रतिशत की दर से विभागी प्रभारों की वसूली की जावेगी।

(ii) आर. आर. केवल बैंक के माध्यम से रजिस्टर्ड लिफाफे में भेजी जानी चाहिए।

(iii) यदि क्रेता अधिकारी माल को पैसेन्जर ट्रेन से भिजवाने की इच्छा करता है तो सम्पूर्ण रेल का भाडा विभाग द्वारा वहन किया जावेगा।

(iv) भुगतान करने पर किये गये प्रेषण प्रभार (Remittance charges) बोलीदाता द्वारा वहन किए जावेगे।

बोलीदाता के उत्तरदाता

32. बीमा -

- (i) सामान गन्तव्य गोदाम पर सही दशा में सुपुर्द किए जावेंगे । यदि सप्लायर चाहे तो वह मूल्यवान सामान को चोरी, नाश या क्षय द्वारा या आग, बाड, मौसम में पडा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे युद्ध, विद्रोह, दंगे आदि) द्वारा हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा । यह बीमा प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा यदि ऐसे व्यय किये जाते है तो राज्य से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जावेगी ।
- (ii) यदि केता द्वारा चाहा गया हो तो केता की लागत पर भी इन वस्तुओं का बीमा कराया जाएगा । ऐसे मामलों में बीमा सदैव भारतीय जीवन बीमा निगम या उसकी सहायक शाखाओं से कराया जाना चाहिए ।

33. भुगतान -

- (i) दुर्लभ एवं विशिष्ट मामलों के सिवाय अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा । यदि अग्रिम भुगतान किया जा रहा हो तो वह माल प्रेषित करने के सबूत पर तथा रेल/प्रतिष्ठित गुडस ट्रान्सपोर्ट कम्पनियों आदि द्वारा वित्तीय शक्तियों में विहित की गई सीमा तक तथा पूर्व निरीक्षण, यदि कोई हो, किए जाने पर दिया जाएगा । अवशेष राशि का भुगतान माल अच्छी हालत में प्राप्त होने पर तथा बोलीदाता को नहीं दिए गए उस सम्बन्ध का प्रमाण पत्र निरीक्षण के समय पृष्ठांकित किये जाने पर दिया जाएगा ।
- (ii) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान बोलीदाता द्वारा केता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किए जायेंगे ।
- (iii) विवादास्पद मदों के सम्बन्ध में, राशि के 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जावेगा ।
- (iv) उन मामलों के सम्बन्ध में जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब वे परीक्षण कर लिए जायेंगे तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप होंगे ।

34. (i) बोली प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल बोलीदाता केता अधिकारी से फर्म आर्डर के प्राप्त होने से अवधि के भीतर सप्लाई करेगा ।

(ii) परिनिर्धारित क्षति (Liquidated damages)- परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में बोलीदाता सप्लाई करने में असफल रहा तो प्रचलित नियमानुसार परिनिर्धारित क्षति प्रदायकर्ता से वसूल की जावेगी ।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

(4) याद प्रदायकता (सप्लायर) किन्हीं बाधाओं के कारण सावेदान्तगत माल को सप्लाइ को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाइ पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(5) यदि माल की सप्लाइ करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई है तो सुपुदर्गी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

35. वसूलियां— परिनिर्धारित क्षयों, कम सप्लाइ, टूट फूट, रद्द की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। कम सप्लाइ, टूट फूट रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षय (लिक्विडेटेड डेमेजेज) के साथ वसूली उनकी देय राशि (ड्यूज) एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पीडी आर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
36. बोलीदाताओं को यदि आवश्यक हो तो आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी चाहिए।
37. यदि बोलीदाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि केता अधिकारी द्वारा जारी किए गए बोली स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लिखित न किया गया हो।
38. केता अधिकारी किसी भी बोली को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बोली नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए बोली ने बोली दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को स्टोर्स की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।
39. बोलीदाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा —
 - 1) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अभिप्रमाणित प्रति।
 - 2) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार आफ फर्मस के पास पंजीकृत है तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।
 - 3) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।
 - 4) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

बोलीदाता के उत्तरदायक

40. यदि संविदा के निर्वचन (Interpretation), आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जावेगा जो उस विवाद के लिए एक मात्र मध्यस्थ (सोल आबिट्रेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उप अधिकारी की नियुक्ति करेगा । यह उप अधिकारी इस संविदा से संबद्ध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा ।
41. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा राजस्थान में जयपुर स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी अन्यत्र पेश नहीं की जाएगी।
42. बोलीदाता को दर GST व अन्य समस्त करों सहित प्रस्तुत करनी होगी।
43. बिड़ संबंधित किसी भी निर्णय के विरुद्ध प्रथम अपील निदेशक प.रा.वि. एवं द्वितीय अपील सचिव प.रा.वि होंगे।
44. इस विविदा एवं अनुबंध के संबंध में अन्य शर्तें एवं नियम जिनका उल्लेख नहीं किया गया है। RTPP 2012 एवं 2013 के प्रावधानों के अनुसार होगी।

मैंने प.रा.वि जयपुर की समस्त शर्तों का अध्ययन कर लिया है तथा मैं इनसे सहमत हूँ एवं इनके पालन करने का वचन देता/देती हूँ तथा निर्धारित परिशिष्ट..... में घोषणा हस्ताक्षर कर संलग्न कर दी गई है।

दिनांक

हस्ताक्षर बिड़दाता
मय मोहर

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:
 - a. have controlling partners/ shareholders in common; or
 - b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 - c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
 - d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
 - e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
 - f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
 - g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to for procurement of in response to their Notice Inviting Bids No..... Dated..... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:

Place:

Signature of bidder

Name :

Designation:

Address:

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is _____

The designation and address of the Second Appellate Authority is _____

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- (2)** The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (3)** If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a)** determination of need of procurement;
- (b)** provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c)** the decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d)** cancellation of a procurement process;
- (e)** applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

- (a)** An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b)** Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

Doc 1

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal Noof

Before the (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii) Official address, if any:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:

.....
.....
..... (Supported by an affidavit)

7. Prayer:

.....
.....

Place

Date

Appellant's Signature

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.